

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3119

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2025 को दिया जाना है

28 फाल्गुन, 1946 (शक)

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में राजस्व बढ़ाना

3119. श्रीमती मंजू शर्मा:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में राजस्व बढ़ाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार की इलेक्ट्रॉनिक संघटकों के घरेलू विनिर्माण में वृद्धि करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार का देशभर में क्षेत्रीय भाषाओं में कम्प्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों की उपलब्धता में वृद्धि करने का विचार है; और
- (ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का वैश्विक स्तर पर अग्रणी स्थान है और यह निर्यातों की वृद्धि तथा रोजगार के अवसरों के सृजन में उत्तरोत्तर योगदान देता रहा है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नैसकॉम) के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 (ई) में 5.8 मिलियन से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कर 224 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात सहित भारत के आईटी उद्योग के 283 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने देश भर में आईटी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों की शुरुआत की है जिसमें भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों के 67 केंद्रों की स्थापना, 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), छोटे कस्बों/शहरों के लिए बीपीओ प्रोत्साहन योजनाएं, राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति-2019 (एनपीएसपी 2019), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट) के 55 केंद्रों के माध्यम से विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम,

आईटी पेशेवरों के पुनः कौशलन /कौशल उन्नयन के लिए फ्यूचर स्किल्स प्राइम, प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन और उद्यमियों के विकास के माध्यम से स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने (टाइड 2.0), उत्पाद नवाचार, विकास और वृद्धि के लिए एमईआईटीवाई का स्टार्टअप एक्सीलेटर (समृद्ध), डोमेन विशिष्ट उत्कृष्टता केंद्र (सीओई), अभिनव स्टार्टअप के लिए जेन-नेक्स्ट सपोर्ट (जेनेसिस) आदि शामिल हैं। इन पहलों ने आईटी उद्योग के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

(ग) सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर सहित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और उपकरणों में बड़े निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2019 (एनपीई 2019) को अधिसूचित किया, जिसके तहत मंत्रालय द्वारा क्रमशः 34,193 करोड़ रुपये और 17,000 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, 3,285 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ इलेक्ट्रॉनिक घटक और सेमिकंडक्टर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना(एस पी ई सी एस) और 3,762 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर 2.0 (ईएमसी 2.0) योजना प्रारम्भ की है। इसके अलावा, सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था।

(घ) और (ङ): जुलाई 2022 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय भाषा प्रौद्योगिकी मिशन (भाषिनी), सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं के लिए भाषिनी मंच (<https://bhashini.gov.in>) के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) संचालित भाषा प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। सभी के लिए किसी भी एप्लिकेशन के साथ एकीकृत करने के लिए भाषिनी एपीआई (<https://apisetu.gov.in>) उपलब्ध हैं।
